समक्ष एस.एस संधावलिया, मुख्य न्यायमूर्ति और एम.एम

पूँछी, माननीय न्यायमूर्ति।

सोहन लाल – ***याचिकाकर्ता***

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, – **प्रतिवादियों**

1980 **का सिविल व्रिट याचिका संख्या** 1403

23 अप्रैल, **1981**

पंजाब नगर सुधार अधिनियम (1922 का 4) - धारा 58, 59, 60, 62, 63 और 65 - भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1984 का 1) - धारा 18 - एक विकास योजना के लिए एक सुधार ट्रस्ट द्वारा अधिग्रहित भूमि - कलेक्टर का पुरस्कार मुआवजे का निर्धारण - मुआवजे में वृद्धि का मामला धारा 59 के तहत ट्रिब्यूनल को भेजा गया - ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष मुआवजा बढ़ाने वाला पुरस्कार दे रहे हैं - पुरस्कार प्रदान करते समय एक या दोनों मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति - क्या यह उसे ख़राब कर रहा है - भूस्वामी इसमें भाग ले रहे हैं ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही - कार्यवाही के किसी भी चरण में मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति के संबंध में आपत्ति नहीं

उठाई गई - ऐसी आपत्ति - क्या उच्च न्यायालय में पहली बार उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

अभिनिर्णित, पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 की प्रासंगिक धाराओं की बारीकी से और गहराई से जांच करने से विधायी मंशा का स्पष्ट संकेत मिलता है कि ट्रिब्यूनल की धुरी इसका अध्यक्ष है जबकि इसके दो मूल्यांकनकर्ता पूरी तरह से सहायक हैं। हालाँकि कार्यवाही में मूल्यांकनकर्ताओं की भागीदारी वांछनीय हो सकती है, लेकिन उनकी उपस्थिति इसकी कार्यवाही के लिए किसी भी तरह से अनिवार्य या महत्वपूर्ण नहीं है। हालाँकि, यह निष्कर्ष अधिनियम के किसी एक या एकान्त प्रावधान से नहीं, बल्कि उनमें से विभिन्न प्रावधानों से लिया गया है, जिसे जब एक योजनाबद्ध संपूर्ण के रूप में देखा जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पुरस्कार प्रदान करने के समय भी दो मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति को डिज़ाइन नहीं किया गया था। कार्यवाही के लिए घातक हो. विधानमंडल ने जानबूझकर और जानबूझकर "मूल्यांकनकर्ता" शब्द का उपयोग किया है और इसका काफी महत्व है। ये व्यक्ति न्यायाधिकरण के सख्त सदस्य नहीं हैं बल्कि राष्ट्रपति के मूल्यांकनकर्ता हैं। वे अनिवार्य रूप से न्यायालय या न्यायाधिकरण की सहायता और सहायता के लिए हैं। वे मूल रूप से स्वयं न्यायालय या न्यायाधिकरण नहीं हैं, बल्कि उसके अधीनस्थ अंग हैं जिनका कार्य स्पष्ट रूप से गौण और प्रकृति में सलाहकार है। यद्यपि मूल्यांकनकर्ताओं को राष्ट्रपति की सहायता करनी है, लेकिन

क़ानून यह कहीं भी निर्धारित नहीं करता है कि दोनों मूल्यांकनकर्ताओं या उनमें से एक या दूसरे को ट्रिब्यूनल की सुनवाई में हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। न्यायालय की सभी अपेक्षित प्रक्रियात्मक शक्तियाँ केवल ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष में निहित हैं, न कि मूल्यांकनकर्ताओं के संदर्भ में राष्ट्रपति में। यहां तक कि कानून, शीर्षक और प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय न केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जाना है, बल्कि मूल्यांकनकर्ताओं की पूर्ण अनुपस्थिति में भी उन पर विचार और उच्चारण किया जा सकता है, जो इंगित करता है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का कोई अभिन्न अंग नहीं हैं। यहाँ. इस प्रकार, यह माना जाता है कि यदि मूल्यांकनकर्ताओं में से कोई भी मौजूद नहीं है या भूमि की माप, मुआवजे की राशि या लागत के मुद्दों पर राय नहीं देता है, तो अकेले राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार में नाम के लायक कोई कमजोरी नहीं होगी।

(पैरा ***5,7,9,10,15*** और ***18)***

अभिनिर्णित, जहां भूस्वामी ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही में भाग लेते रहे और ट्रिब्यूनल के दो मूल्यांकनकर्ताओं की कथित अनुपस्थिति के खिलाफ अपनी छोटी उंगली नहीं उठाई, उच्च में पहली बार ऐसी आपत्ति उठाना उनके मुंह में झूठ नहीं होगा। अदालत। यह स्पष्ट है कि वे न केवल कार्यवाही के दौरान धरने पर बैठे रहे, बल्कि वास्तव में उन्होंने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया था, और इसलिए, उनके आचरण से यह

माना जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसी किसी भी कमजोरी को स्पष्ट रूप से माफ कर दिया है।

(*पैरा* 1***9***)

(माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी की एक खंडपीठ ने दो महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर अपना निर्णय देने के बाद ***23*** अप्रैल***, 1981*** को मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश के पास भेज दिया***,*** जो प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय के लिए एक खंडपीठ द्वारा उन पर विचार करना आवश्यक हो गया। विद्वान एकल न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी ने अंततः ***2*** अप्रैल***, 1984*** को मामले का फैसला किया)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद ***226*** के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि -

(ए) मामले का रिकॉर्ड मंगवाया जाए***;***

(बी) दिनांक ***21*** दिसंबर***, 1979*** के फैसले को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की जाए***,*** प्रतिलिपि अनुलग्नक पी ***5*** अध्यक्ष***,*** सुधार ट्रस्ट***,*** अंबाला***,*** प्रतिवादी संख्या ***2*** द्वारा पारित की गई है और यह माननीय न्यायालय मूल्यांकन करने में प्रसन्न हो सकता है

*(*सी) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाएगा*;*

*(*डी) उत्तरदाताओं को रिट याचिका की अग्रिम प्रतियों की सेवा से मुक्त किया जाए*;*

*(*ई) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत की अनुमति दी जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की एक तिहाई राशि वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादी नंबर ***5*** किशन सिंह को भुगतान नहीं की जाएगी।

याचिकाकर्ता के लिए पी.एस. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता और वी.एम. जैन, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या ***5*** के लिए यू.डी. गौड़, ए.जी., हरियाणा, एस.के. अग्रवाल, वकील।

निर्णय

एस.एस संधावलिया, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति।

(1) क्या पुरस्कार प्रदान करते समय केवल एक या दोनों मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति। पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट

एक्ट, 1922 की धारा 65 के तहत ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष इसे दूषित कर देंगे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार की गई इन छह संबंधित सिविल रिट याचिकाओं में आम लिंक बनाता है।

(2) चूंकि उपरोक्त प्रश्न पूरी तरह से कानूनी है, और हम यहां प्रत्येक मामले की खूबियों में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, इसलिए सी.डब्ल्यू. 1403/1980 में तथ्यों का संक्षेप में संदर्भ देना पर्याप्त है। याचिकाकर्ता अंबाला शहर में स्थित कुछ भूमि का मालिक था, जिसे विकास योजना संख्या 12 के लिए प्रतिवादी-सुधार ट्रस्ट द्वारा अधिग्रहित किया गया था। नतीजतन, कलेक्टर ने अपना पुरस्कार प्रदान किया जिसमें उन्होंने रुपये की दर से मुआवजे का आकलन किया। 10 प्रति वर्ग गज. याचिकाकर्ता और अन्य जिनकी भूमि इसी तरह अधिग्रहीत की गई थी, ने मामले को बढ़ाने के लिए अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल को संदर्भित करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के साथ पठित पंजाब नगर सुधार अधिनियम (यहां अधिनियम कहा गया है) की धारा 59 के तहत आवेदन किया। मुआवजा दिया गया. इन आवेदनों का ट्रस्ट द्वारा विरोध किया गया और पक्षों की दलीलों पर ट्रिब्यूनल ने 17 जनवरी, 1978 को आवश्यक मुद्दे तय किए। यह उल्लेखनीय है कि इसी तरह के आवेदन अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए गए थे जिनकी भूमि योजना संख्या 12 के लिए अधिग्रहित की गई थी। स्कीम नंबर 5 के लिए भी ट्रिब्यूनल के समक्ष थे और सभी आवेदनों को परीक्षण के लिए समेकित किया गया था और

याचिकाकर्ता के मामले में पूरे साक्ष्य दर्ज किए गए थे। साक्ष्यों को विधिवत दर्ज करने के बाद ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने 21 दिसंबर, 1979 को एक विस्तृत पुरस्कार दिया, जिसके तहत उन्होंने योजना संख्या 12 के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा बढ़ाकर रु. रुपये की जगह 14 रुपये 10 और इसी तरह स्कीम नंबर 5 के लिए रु. रुपये की जगह 17 रु. 13 को कलेक्टर द्वारा पुरस्कृत किया गया। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ ट्रिब्यूनल के उपरोक्त पुरस्कार को इस आधार पर चुनौती दी कि राष्ट्रपति के दो मूल्यांकनकर्ताओं ने संदर्भों के परीक्षण में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया और इसलिए, पूरी कार्यवाही और विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पुरस्कार को चुनौती दी गई। ट्रिब्यूनल पूरी तरह से दूषित है।

(3) हालाँकि इस बिंदु पर दलीलें थोड़ी अस्पष्ट हैं, लेकिन हमारे सामने पार्टियों का स्वीकृत मामला था कि वर्तमान मामले में दो विद्वान अधिवक्ताओं श्री वी.के. गुप्ता और श्री सुखनंदन सिंह को धारा ***60*** के तहत ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के मूल्यांकनकर्ता के रूप में नामित किया गया था। अधिनियम का. न ही यह किसी विवाद में था कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा उन दोनों को विधिवत नोटिस भेजा और तामील किया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी किसी भी स्तर पर कार्यवाही में भाग लेने का विकल्प नहीं चुना। यह सामान्य मामला है कि अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मूल्यांकनकर्ताओं को ट्रिब्यूनल की सुनवाई में उपस्थित होने के लिए बाध्य करता हो।

(4) मूल रूप से धारा ***58*** और धारा ***60*** की उप-धारा (***1)*** पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से श्री जैन ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और दो मूल्यांकनकर्ता शामिल होंगे। इससे यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई कि धारा ***65*** के तहत अंतिम पुरस्कार भी ट्रिब्यूनल का गठन करने वाले सभी तीन व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में, जहां तक धारा ***65 (1)*** ***(***ए) के तहत निष्कर्ष का संबंध है, ये होना चाहिए का हो, समग्र रूप से शरीर। नतीजतन, यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में पुरस्कार केवल राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था, यह अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी से ग्रस्त था और इसलिए, या तो गैर-स्थायी या कम से कम मरम्मत से परे खराब हो गया था।

(5) अधिनियम के भौतिक वैधानिक प्रावधानों की पहली झलक और डी हॉर्स पर, उपरोक्त विवाद में प्रारंभिक तौर पर कुछ हद तक प्रशंसनीयता थी। हालाँकि, इस बिंदु से संबंधित अधिनियम की धाराओं की बारीकी से और गहन जांच से विधायी मंशा का स्पष्ट संकेत मिलता है कि ट्रिब्यूनल की धुरी इसके अध्यक्ष हैं जबकि इसके दो मूल्यांकनकर्ता पूरी तरह से सहायक हैं। हालाँकि कार्यवाही में मूल्यांकनकर्ताओं की भागीदारी वांछनीय हो सकती है, लेकिन उनकी उपस्थिति इसकी कार्यवाही के लिए किसी भी तरह से अनिवार्य या महत्वपूर्ण नहीं है। हालाँकि, यह निष्कर्ष अधिनियम के किसी एक या एकान्त प्रावधान से नहीं, बल्कि उनमें से विभिन्न प्रावधानों से लिया गया है, जिसे जब एक योजनाबद्ध संपूर्ण

के रूप में देखा जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पुरस्कार प्रदान करने के समय भी दो मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति को डिज़ाइन नहीं किया गया था। कार्यवाही को बांधना घातक होगा।

(6) अब इस संदर्भ में सबसे पहले जो बात ध्यान में आती है वह ट्रिब्यूनल के गठन के संबंध में धारा ***58*** और ***60*** के प्रावधान हैं। पूर्व प्रावधान में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ***1894*** के तहत ट्रस्ट के लिए भूमि के अधिग्रहण के संदर्भ में, अदालत के कार्यों को करने के उद्देश्य से, एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। धारा ***60*** का प्रासंगिक भाग जिसका संदर्भ आवश्यक है वह इस प्रकार है:-

"60. (1) न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो मूल्यांकनकर्ता शामिल होंगे।

(2) अधिकरण का अध्यक्ष एक व्यक्ति होगा, **-**

(ए) जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है***;*** या

(बी) जिसने दस साल की अवधि के लिए कलेक्टर का पद संभाला हो***;*** या

(सी) जो क्यूआर की सेवा कर रहा है उसने जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है।

(7) अब उप-धारा (***1)*** पर बारीकी से नजर डालने से पता चलेगा कि "ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल में समान रानी के तीन सदस्य होते हैं जिनमें से एक अध्यक्ष हो सकता है। यदि ऐसा होता, तो यह एक अतिरिक्त स्ट्रिंग होती याचिकाकर्ता का झुकाव। इसके बजाय, इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि

इसमें एक राष्ट्रपति और दो मूल्यांकनकर्ता शामिल होंगे। निम्नलिखित के मद्देनजर, मैं इस बात पर सहमत हूं कि विधायिका ने जानबूझकर और जानबूझकर "मूल्यांकनकर्ता" शब्द का इस्तेमाल किया है और यह निर्णायक नहीं तो पर्याप्त है, लेकिन महत्वपूर्ण है। दोहराने के लिए, ये व्यक्ति न्यायाधिकरण के सख्त सदस्य नहीं हैं बल्कि राष्ट्रपति के मूल्यांकनकर्ता हैं। इस प्रकार उनकी वास्तविक स्थिति उपरोक्त उद्धृत उप-धाराओं (***1)*** और (***2)*** में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है) साथ ही धारा ***60*** की उपधारा (***3),*** हालांकि संदर्भ में आसानी के लिए बाद के प्रावधानों में "सदस्य" शब्द का उपयोग दो मूल्यांकनकर्ताओं के लिए भी परस्पर विनिमय के लिए किया गया है। हालांकि, मेरे विचार से, यह मूल तथ्य के विरुद्ध नहीं होगा कि "मूल्यांकनकर्ता" शब्द कानूनी कला के लिए प्रसिद्ध शब्द है। इनका उद्देश्य अनिवार्य रूप से न्यायालय या न्यायाधिकरण की सहायता करना है। वे मूलतः न्यायालय या न्यायाधिकरण नहीं हैं, बल्कि उसके अधीनस्थ अंग हैं जिनका कार्य स्पष्ट रूप से गौण और प्रकृति में सलाहकार है। वेबस्टर के तीसरे नए अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में, ***"***मूल्यांकनकर्ता" शब्द को निम्नलिखित अर्थ दिए गए हैं: -

"सहायक, न्यायाधीश का सहायक, ***(***पास बैठना, न्यायाधीश के कार्यालय में सहायता करना)***;*** न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए नियुक्त या निर्वाचित व्यक्ति: विशेष रूप से निर्णय किए जाने वाले विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला। ***"***

फिर, बाउवियर्स लॉ डिक्शनरी में, एक "मूल्यांकनकर्ता" को "कानून में कुशल व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे निचली अदालतों के न्यायाधीशों को सलाह देने के लिए चुना गया है।" ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, एक "मूल्यांकनकर्ता" का अर्थ बताया गया है: -

"एक व्यक्ति ने उद्योग के किसी विशेष विज्ञान में सीखा है, जो ऐसे विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले मामले की सुनवाई पर न्यायाधीश के साथ बैठता है और अपनी सलाह देता है। इंग्लैंड में नौवाहनविभाग व्यवसाय में नौपरिवहन या नाविकता के प्रश्नों से जुड़े मामलों में मूल्यांकनकर्ताओं को बुलाने की प्रथा है। उन्हें 'समुद्री मूल्यांकनकर्ता' (क्यू.वी.) कहा जाता है, और वे हमेशा ट्रिनिटी हाउस के भाई होते हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि विधायिका ने उनकी दोयम दर्जे को उजागर करने के लिए ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के खिलाफ "मूल्यांकनकर्ता" शब्द का इस्तेमाल किया है।

(8) राष्ट्रपति और दो मूल्यांकनकर्ताओं के बीच यह तीव्र अंतर इस तथ्य से और भी स्पष्ट है कि क़ानून राष्ट्रपति की न्यूनतम योग्यताओं का सावधानीपूर्वक प्रावधान करता है। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति होगा। विकल्प में, धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) में ऐसे व्यक्ति का बुनियादी प्रशासनिक अनुभव निर्धारित किया गया है, जिसने या तो 10 साल की अवधि

के लिए कलेक्टर का पद संभाला हो या जिला मजिस्ट्रेट के रूप में सेवारत या कार्य कर चुका है। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि राष्ट्रपति केवल न्यूनतम न्यायिक या प्रशासनिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही हो सकता है। जहां तक मूल्यांकनकर्ताओं का संबंध है, उसके तीव्र अनुबंध में, वही क़ानून किसी भी योग्यता खंड का कम से कम उल्लेख नहीं करता है। वास्तव में, उप-धारा (3) इंगित करेगी कि दो मूल्यांकनकर्ताओं को किसी भी शैक्षणिक या न्यायिक योग्यता के बिना नियुक्त किया जा सकता है। उनमें से एक उस विशेष शहर की नगरपालिका समिति से अधिक किसी प्राधिकारी से उत्पन्न नहीं होगा जिसके लिए ट्रिब्यूनल को कार्य करना है क्योंकि क़ानून ने ऐसी नगरपालिका समिति को नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित किया है। इसलिए, एक ओर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और दूसरी ओर दो मूल्यांकनकर्ताओं के बीच तीव्र विरोधाभास एक तरह से बहुत ही सीमा पर प्रकट होता है।

(9) नोटिस के लिए अगली बात यह तथ्य है कि यद्यपि मूल्यांकनकर्ताओं को राष्ट्रपति की सहायता करनी है, क़ानून कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि या तो दोनों मूल्यांकनकर्ताओं या उनमें से एक या दूसरे को ट्रिब्यूनल की सुनवाई में हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। यदि क़ानून का यह इरादा होता कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसे दो या कम से कम एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा सहायता न मिले, तो आम तौर पर (हालांकि जरूरी नहीं) विधायिका ने अपने

विवेक से न्यूनतम प्रावधान किया होता न्यायाधिकरण का कोरम. माना कि ऐसा नहीं किया गया है. वास्तव में, ऐसा होने से बहुत दूर, क़ानून, जैसा कि इसके बाद स्पष्ट होगा, वास्तव में न केवल एक बल्कि दोनों मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति के संदर्भ में कल्पना करता है और स्पष्ट रूप से उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही को पूरी वैधता प्रदान करता है। इस पहलू पर अधिक विस्तृत चर्चा अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के संदर्भ में होती है।

(10) अधिनियम की धारा 59 फिर से ट्रिब्यूनल को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत न्यायालय के कार्यों के बराबर करने का प्रयास करती है, जिस पर इसकी कार्यवाही मूल रूप से मॉडलिंग की जानी है। यह रेखांकित करने योग्य है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, अधिग्रहण न्यायालय जिले में प्रमुख मूल नागरिक क्षेत्राधिकार का न्यायालय है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसके प्रावधानों को मूलतः संशोधनों के साथ लागू किया जाना है, यह माना जाता है कि किसी भी अधिग्रहण अदालत को आवश्यक रूप से मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता से कार्य करने की कल्पना नहीं की गई है। किसी विशेष मामले में ट्रिब्यूनल की कार्यवाही की शुरुआत में, अधिनियम की धारा 59 (सी) लागू होगी और इसके प्रावधान व्यापक रूप से नोटिस की मांग करेंगे: -

"59. ट्रस्ट के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ***1894*** के तहत भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से-

*(*ए) ** ** ** **

*(*बी) ** ** ** ^ **

*(*सी) ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के पास गवाहों को बुलाने और उनकी उपस्थिति को लागू करने और दस्तावेजों के उत्पादन को मजबूर करने की शक्ति होगी, उसी तरीके से और (जहाँ तक हो सकता है) उसी तरीके से जैसा कि मामले में प्रदान किया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता, ***1908*** के तहत एक सिविल न्यायालय की;"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि न्यायालय की सभी अपेक्षित प्रक्रियात्मक शक्तियाँ केवल ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष में निहित हैं, न कि मूल्यांकनकर्ताओं के संदर्भ में राष्ट्रपति में। यह फिर से इस तथ्य का सूचक है कि मूल्यांकनकर्ता ट्रिब्यूनल का अभिन्न अंग होने के बजाय सहायक सहायकों की प्रकृति में हैं। इसलिए, परिणाम यह है कि गवाहों को बुलाने और उनकी उपस्थिति को लागू करने, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के सभी अनिवार्य बल के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और प्रस्तुत करने की भौतिक शक्तियां ट्रिब्यूनल के मूल्यांकनकर्ता अध्यक्ष के पास हैं।

(11) इस संदर्भ में धारा 62 और 63 के प्रावधानों का भी संदर्भ दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ट्रिब्यूनल के कर्मचारियों और कार्यों का प्रशासनिक प्रमुख दो मूल्यांकनकर्ताओं के पूर्ण बहिष्कार के लिए उसका अध्यक्ष है। ट्रिब्यूनल के कामकाज को चलाने के लिए कर्मचारियों

आदि को निर्धारित करने की शक्ति, देय वेतन की राशि और नियुक्ति, निष्कासन और बर्खास्तगी की शक्ति सभी राष्ट्रपति में निहित हैं। इसी प्रकार, कर्मचारियों और दोनों मूल्यांकनकर्ताओं को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक आदि ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रपति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है जो इसे आगे वितरित करता है। यह राष्ट्रपति की अतिरिक्त प्रशासनिक प्रमुखता को भी उजागर करता है जबकि दोनों मूल्यांकनकर्ता इस क्षेत्र में बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं और वास्तव में राष्ट्रपति उनके लिए संवितरण प्राधिकारी भी हैं।

(12) अगली महत्वपूर्ण बात जो शायद दोहराव और पुनरावृत्ति दोनों के लायक है, वह यह है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ट्रिब्यूनल की सुनवाई में दोनों या किसी एक मूल्यांकनकर्ता की उपस्थिति को दूर से भी बाध्य कर सके। धारा ***61*** के संदर्भ से पता चलेगा कि मूल्यांकनकर्ताओं को भुगतान का एक तरीका फीस के रूप में है। क्या, किसी विशेष मामले में, कोई मूल्यांकनकर्ता शुल्क स्वीकार करेगा, या आम तौर पर उपस्थित होना चाहेगा, यह प्रावधानों में निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति और उस मामले में किसी अन्य प्राधिकारी के पास दोनों मूल्यांकनकर्ताओं में से किसी को भी उपस्थित होने के लिए बुलाने या बाध्य करने की कोई शक्ति नहीं है। वर्तमान मामला एक तरह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस तथ्य को उजागर करता है कि पूर्ण सूचना के बावजूद दोनों मूल्यांकनकर्ताओं में से किसी ने भी किसी भी स्तर पर कार्यवाही के साथ खुद को जोड़ने का विकल्प

नहीं चुना था, हालांकि उन्हें ***2-3*** साल की अवधि के लिए लंबे समय तक खींचा गया था। स्पष्ट रूप से, इसलिए, कानून मूल्यांकनकर्ताओं के लिए उपस्थित होना अनिवार्य नहीं बनाता है और न ही सुनवाई में उनकी गैर-उपस्थिति के लिए किसी दंड का प्रावधान करता है। इसलिए, मूल्यांकनकर्ताओं को ट्रिब्यूनल के एक अभिन्न अंग के रूप में कल्पना करना मुश्किल है जहां न तो वे उपस्थित होने के लिए कानूनी दायित्व के तहत हैं और न ही उनकी गैर-उपस्थिति से कोई प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न होता है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि विधायिका ऐसी स्थिति का सामना करना चाहती है जहां एक मूल्यांकनकर्ता या मूल्यांकनकर्ता, अपनी गैर-भागीदारी से, मुआवजे का निर्धारण करने के लिए पूरी कार्यवाही को गैर-स्थायी रूप से प्रस्तुत कर दे।

(13) हालाँकि, यह धारा ***65(1)(***बी) और उपधारा (***2)*** के प्रावधान हैं***;*** उसके: जो सत्य के सबसे स्पष्ट संकेतक हैं (अधिकरण के अध्यक्ष के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की स्थिति इस पहलू की सराहना करने के लिए, धारा ***65*** को पहले पढ़ा जा सकता है: -*

"65. (1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ***1894*** के तहत न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पुरस्कार का निर्धारण करने के उद्देश्य से-

(ए) यदि भूमि की माप, या मुआवजे की राशि या लागत की अनुमति के संबंध में कोई असहमति है, तो न्यायाधिकरण के अधिकांश सदस्यों की राय मान्य होगी***;***

*(*बी) पूर्वगामी खंड में निहित किसी भी बात के बावजूद, कानून और शीर्षक और प्रक्रिया के सभी प्रश्नों पर निर्णय पूरी तरह से न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पास होगा, और ऐसे प्रश्नों की सुनवाई और निर्णय मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उनकी उपस्थिति को आवश्यक मानते हैं।

(2) इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति में किसी भी मामले पर साक्ष्य दर्ज कर सकता है जब तक कि वह उनकी उपस्थिति को आवश्यक नहीं समझता।

(3) ट्रिब्यूनल का हर पुरस्कार, और पैसे के भुगतान के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया हर आदेश, लघु वाद न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा, या यदि ऐसा कोई न्यायालय नहीं है, तो स्थानीय सीमा के भीतर वरिष्ठ उप-न्यायाधीश द्वारा लागू किया जाएगा। यह जिसके अधिकार क्षेत्र का था, ऐसा बना दिया गया मानो यह उसी न्यायालय का डिक्री हो।***"***

(14) पूर्वोक्त उप-धारा (***2)*** में सबसे पहले, यह सूचित नोटिस की मांग करता है कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति में अकेले कार्यवाही का संचालन करने के हकदार हैं जब तक कि वह उनकी उपस्थिति को आवश्यक नहीं मानते। व्यावहारिक रूप से, इसलिए, किसी भी मुआवजे के मामले में पूरे साक्ष्य को रिकॉर्ड करना राष्ट्रपति के विवेक के अंतर्गत होगा, हालांकि, मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति में इसका आयात

महत्वपूर्ण हो सकता है। यह उपधारा संशोधन अधिनियम (हरियाणा अधिनियम, ***1974*** का ***35)*** द्वारा डाली गई थी। अब इस संशोधन का आशय स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि पूरे साक्ष्य या उसके एक बड़े हिस्से को दोनों मूल्यांकनकर्ताओं की पूर्ण अनुपस्थिति में दर्ज किया जा सकता है, तो यह स्पष्ट रूप से संकेत देगा कि वे ट्रिब्यूनल का अभिन्न अंग नहीं हैं जिसका कार्य मूल रूप से न्यायिक है। यह स्वयंसिद्ध है कि एक न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय, जिसे साक्ष्य के आधार पर किसी मामले का फैसला करना होता है, सामान्य तौर पर (हालांकि हमेशा नहीं) इसे अपनी उपस्थिति में दर्ज करेगा। वास्तव में, बड़े न्यायिक परिप्रेक्ष्य में, यह बार-बार कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को गवाहों को बॉक्स में देखने का लाभ मिलता है, इस विशेष तथ्य के आधार पर वह अनिवार्य रूप से बेहतर स्थिति में है। किसी भी मामले में, न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग उसके कार्य का एक हिस्सा है और जहां कानून स्वयं प्रदान करता है कि मूल्यांकनकर्ता पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं, तो निहित इरादे से यह माना जाएगा कि उन्हें समान रूप से अभिन्न नहीं माना जाता है ऐसे न्यायाधिकरण का हिस्सा।

(15) फिर भी, उपरोक्त उपधारा (***2)*** अलग नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से उप-धारा (***1)*** के पूर्ववर्ती खंड (बी) के और भी महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। संक्षेप में यह प्रदान करता है कि परीक्षण के दौरान सभी भौतिक प्रश्नों पर, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है या वास्तव

में इसे और अधिक सटीक रूप से कहें तो, ऐसा निर्णय दोनों मूल्यांकनकर्ताओं के बहिष्कार के लिए पूरी तरह से उनके पास होता है। यह न्यायाधिकरण के समक्ष उठने वाले कानून के सभी प्रश्नों, स्वामित्व के सभी प्रश्नों, जिनके निर्धारण की आवश्यकता हो सकती है और प्रक्रिया के सभी प्रश्नों, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों, के संबंध में स्पष्ट रूप से है। इस प्रकार "केवल" शब्द का उपयोग और इसके सार्थक क्षेत्र से मूल्यांकनकर्ताओं का पूर्ण बहिष्कार स्पष्ट है। भले ही मामला वहीं पर रुका हो, याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क के लिए कुछ जगह हो सकती है, लेकिन उपरोक्त खंड (बी) में यह भी प्रावधान है कि इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सुनवाई और निर्धारण दोनों की अनुपस्थिति में अकेले राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। मूल्यांकनकर्ता जब तक राष्ट्रपति उनकी उपस्थिति को आवश्यक नहीं समझते। इस प्रकार, कानून, शीर्षक और प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी न केवल राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, बल्कि मूल्यांकनकर्ताओं की पूर्ण अनुपस्थिति में भी उन पर विचार किया जा सकता है और सुनाया जा सकता है, जो इंगित करता है कि वे निर्णय का अभिन्न अंग नहीं हैं। यहां बनाने की प्रक्रिया. ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने सलाहपूर्वक मूल्यांकनकर्ताओं को मामले के महत्वपूर्ण और भौतिक पहलू से बाहर रखा और उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर कर दिया था।

(16) जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस मुद्दे को किसी एकान्त प्रावधान या पृथक पहलू के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह बड़े योजनाबद्ध परिप्रेक्ष्य पर है और प्रासंगिक प्रावधानों की समग्रता की पृष्ठभूमि के साथ, किसी को धारा ***65(***एल)(ए) के प्रावधानों का विज्ञापन और अर्थ करना होगा। यह निर्धारित किया गया है कि भूमि की माप, मुआवजे की राशि या लागत के संबंध में असहमति की स्थिति में, बहुमत की राय मान्य होगी। मेरी राय में, असहमति की घटना इस प्रावधान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। असहमति स्वाभाविक रूप से मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति और उनके द्वारा एक राय प्रस्तुत करने पर आधारित होगी जो दूसरे के विपरीत हो सकती है। यदि वे न तो उपस्थित हैं और न ही मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, तो किसी भी असहमति का कोई सवाल ही नहीं उठता है और न ही बहुमत की राय की प्रधानता की आवश्यकता है। इसलिए, धारा ***65(1) (***ए) मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति और राय प्रक्रिया को पूर्व मानती है। यदि इन दोनों चीजों में से कोई भी एक साथ अस्तित्व में नहीं है तो खंड (ए) शायद ही लागू होगा। फिर, इसके अलावा, क्या होगा यदि मूल्यांकनकर्ताओं ने, जैसा कि वर्तमान मामले में है, कार्यवाही के किसी भी चरण में खुद को कभी भी संबद्ध नहीं किया है***?*** क्या होगा यदि उन्होंने कभी भी साक्ष्य नहीं सुना है, और यहां तक कि जब अधिकार, शीर्षक और प्रक्रिया के सार्थक मुद्दों पर निर्णय लिया गया था तब भी वे उपस्थित नहीं रहे थे***;*** न ही न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क

प्रस्तुत करने पर किसी भी पक्ष को मामले की सुनवाई का लाभ मिलता है*?* इन संभावनाओं के आलोक में ही इस प्रावधान को समझना होगा। इससे और इस संदर्भ में देखे गए पहले के प्रावधानों से जो कुल प्रभाव निकलता है, वह यह है कि यदि खंड (ए) का कोई अर्थ है और संभवतः इसका उचित अनुप्रयोग हो सकता है, तो यह केवल इस धारणा पर है कि पुरस्कार प्रदान करते समय वास्तव में, मूल्यांकनकर्ता उपस्थित होते हैं और उनके पास पेश करने के लिए एक राय होती है जो राष्ट्रपति या एक-दूसरे से भिन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप असहमति होती है। यदि वे भूमि की माप या मुआवजे की राशि या लागत के भौतिक मुद्दों पर न तो मौजूद हैं और न ही उनकी कोई राय है, तो इन प्रावधानों का कोई अंतर-प्रभाव नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उप-धारा ***65(1)*** के खंड (ए) को पढ़ने का एकमात्र उचित तरीका यह है कि यह केवल उस स्थिति में लागू होगा जहां मूल्यांकनकर्ता वास्तव में मौजूद हैं और पुरस्कार निर्धारित करने के उद्देश्य से राय देना चुनते हैं। इसलिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी वास्तविक उपस्थिति और भागीदारी प्रावधानों में अंतर्निहित है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहां भी क़ानून मूल्यांकनकर्ताओं में से केवल एक के उपस्थित होने और राष्ट्रपति के साथ मतभेद चुनने की स्थिति का प्रावधान नहीं करता है।

(17) किसी को भी व्याख्या की प्रसिद्ध कहावत को समान रूप से याद रखना चाहिए कि किसी प्रावधान की व्याख्या

इस तरीके से की जानी चाहिए जो क़ानून को व्यावहारिक बनाए। यदि यह माना जाए कि पुरस्कार तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों मूल्यांकनकर्ता राष्ट्रपति के साथ उपस्थित न हों और उस पर अपनी राय दर्ज न करें, तो पुरस्कार प्रदान करना ही बाधित और मरणासन्न हो सकता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम धारा ***65(1)(***ए) के तहत पुरस्कार निर्धारित करने के अंतिम और अंतिम चरण में भी मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति को बाध्य करने और लागू करने का कोई प्रावधान नहीं करता है। इसलिए, कोई मुआवजे के लिए लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे की कल्पना कर सकता है, जो नागरिकों को भौतिक रूप से प्रभावित कर रहा है, स्थिर पड़ा हुआ है और निर्णय लेने में असमर्थ है क्योंकि मूल्यांकनकर्ताओं में से एक या अन्य ने पुरस्कार प्रदान करने में भाग लेने या राय देने का विकल्प नहीं चुना है। इस तरह का निर्माण, वास्तव में, नागरिकों को मुआवजा देने के सभी प्रावधानों को पूरी तरह से अप्रभावी बना सकता है और किसी भी मामले में व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं की अजीब सनक के अधीन हो सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा ***65(1)*** के खंड (ए) के प्रावधानों में "यदि मौजूद है" शब्दों को पढ़ना उचित और आवश्यक दोनों है।

(18) इसलिए, निष्कर्ष निकालने के लिए मैं यह मानूंगा कि यदि मूल्यांकनकर्ताओं में से कोई भी उपस्थित नहीं है

या भूमि की माप, मुआवजे की राशि या लागत के मुद्दों पर राय नहीं देता है, तो अकेले राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार में नाम के लायक कोई कमी नहीं होगी। इसलिए, शुरुआत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए।

(19) अब उपरोक्त के अलावा, हम विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा के दृढ़ रुख से भी समान रूप से प्रभावित हैं कि ***2-3*** वर्षों तक चले लंबे मुकदमे में किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता ने अपनी छोटी उंगली नहीं उठाई। ट्रिब्यूनल के दो मूल्यांकनकर्ताओं की कथित अनुपस्थिति के खिलाफ। साक्ष्य दर्ज करने और प्रक्रिया, शीर्षक और कानून के मुद्दों के प्रश्नों के निर्धारण के सभी चरणों में ऐसा ही था। भले ही यह कहा जा सकता है कि इन्हें कानूनी रूप से दो मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति में आयोजित किया जा सकता है, याचिकाकर्ता की ओर से यह स्वीकार करना होगा कि कम से कम माप के मुद्दों पर राष्ट्रपति के समक्ष अंतिम बहस के चरण में भूमि, मुआवज़े या लागत की राशि के संबंध में, मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति के बारे में तत्काल और बलपूर्वक आपत्ति उठाई जा सकती है। माना जाता है कि ऐसी किसी भी आपत्ति का संकेत कभी नहीं उठाया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यहां याचिकाकर्ता कार्यवाही के दौरान न केवल बाड़े में बैठे रहे, बल्कि वास्तव में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा अकेले बैठे निर्णय को सक्रिय रूप से आमंत्रित किया गया था। इसलिए, अब याचिकाकर्ता

के मुंह से आपत्ति उठाना उचित नहीं है और न ही किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकृति। पूरी तरह से तर्क के लिए (यहां तक कि दूर से भी ऐसा किए बिना) यह मानते हुए कि पुरस्कार प्रदान करने के चरण में मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति और भागीदारी आवश्यक है, याचिकाकर्ता को अपने आचरण से स्पष्ट रूप से किसी भी छूट को माफ कर दिया गया माना जाना चाहिए उसमें ऐसी दुर्बलता. इस पहलू पर उदाहरणों की एक लंबी श्रृंखला है और मेसर्स पन्नालाल बिनीराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (***1)*** मामले में उनके आधिपत्य की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना पर्याप्त है: -

"इसके अलावा एक और विशेषता है जो इन दोनों समूहों के लिए सामान्य है और वह यह है कि किसी भी याचिकाकर्ता ने अपने मामलों को ऊपर बताए गए तरीके से स्थानांतरित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई और वास्तव में उन आयकर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया जिनके पास उनका मामला है। मामले स्थानांतरित कर दिए गए थे. ***20*** मार्च ***1950*** को बीड़ी सप्लाई गो. बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया (***2)*** में हमारे फैसले के बाद ही ये याचिकाकर्ता जाग गए और ***20*** अप्रैल ***1956*** को अमृतसर समूह ने अपने कथित अधिकारों का दावा किया। और रायचूर समूह पर। ***5*** नवंबर ***1956***। यदि वे उन आयकर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से सहमत हैं जिनके पास उनके मामले स्थानांतरित किए गए थे, तो वे निश्चित रूप से अनुच्छेद ***32*** के तहत इस न्यायालय के

अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के हकदार नहीं थे। यह अच्छी तरह से तय है कि याचिकाकर्ताओं का ऐसा आचरण उन्हें अधिकार से वंचित कर देगा और उन्हें इस न्यायालय के हाथों कोई राहत मिलेगी।***"***

(20) नानाई लाई एडवोकेट बनाम डॉ. प्रेरणा चंद सिंघवी और अन्य (***3)*** में टिप्पणियाँ समान प्रभाव और कुछ मामलों में और भी अधिक निर्णायक हैं। पुंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ बनाम विजय सिंह लांबा आदि, ***(4);*** जगज कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, फगवाड़ा बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटियाला और अन्य, ***(5);*** दविंदर सिंह और अन्य बनाम उप सचिव सह-निपटान आयुक्त, ग्रामीण, पुनर्वास विभाग, पंजाब और अन्य (***6);*** अतर सिंह और अन्य बनाम होरियाना राज्य और अन्य, ***(7):*** राम नाथ बनाम रमेश और अन्य, ***(8);*** ओ.ए.ओ.के. लैचमनन चटियार बनाम मद्रास निगम आयुक्त और अन्य, ***(9);*** और परिवहन प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश द्वारा। इसके सचिव एवं अन्य द्वारा हैदराबाद (***10)***।

(21) उपरोक्त के मद्देनजर, हमें प्रतिवादी-राज्य की आपत्ति को भी बरकरार रखना चाहिए कि इन सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं को धारा ***65(1)*** के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति पर पहली बार आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।) (ए) क्योंकि उन्होंने कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया है और

ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा निर्णय को आमंत्रित किया है जो भौतिक रूप से उनके पक्ष में भी जाता है।

(22) दो महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर पूर्वोक्त निर्णय देने के साथ, जिन पर डिवीजन बेंच द्वारा विचार करना आवश्यक हो गया था, हम पार्टियों के विद्वान वकील की आम प्रार्थना को स्वीकार करेंगे कि इन मामलों को अब एक विद्वान एकल न्यायाधीश के पास भेजा जाए। प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय। तदनुसार आदेश दिया गया है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा